नईदुनिया

मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की छलांग

जगत प्रकाश नड्डा

भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जांच केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है, जिनका केंद्र आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इन लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है कि देश में लोगों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कमी आई है। यह खर्च पहले 65 प्रतिशत तक था, जो अब घटकर 43 प्रतिशत रह गया है।

जिला अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु से लेकर बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर मरीज तक, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसेमंद, अच्छी गुणवत्ता वाले और किफायती चिकित्सा उपकरण बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने, बीमारियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब जोर एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने पर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय मजबूत बनाना है।

पहले ,भारत कई आधुनिक और जटिल चिकित्सा उपकरणों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर था। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे इलाज की लागत बढ़ी, आपूर्ति व्यवस्था पर बाहरी निर्भरता बनी रही और इन उपकरणों की पहुंच सीमित रही। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में देश के भीतर आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाना और जांच की लागत कम करना है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्क और दवा एवं चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना शामिल हैं।

इन पहलों से देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नए शोध, निवेश और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से अधिक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का देश में

उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि भारत धीरे-धीरे दुनिया के चिकित्सा तकनीक क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है।

सिर्फ चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आधुनिक जांच सुविधाओं, शरीर की अंदरूनी तस्वीर लेने वाली मशीनों, शरीर में लगाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों, गहन चिकित्सा की मशीनों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही इलाज की गुणवत्ता और समय पर इलाज मिलने में भी सुधार होता है। देश में ही चिकित्सा उपकरण बनने से विदेशों से आयात पर निर्भरता घटती है, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होती है और लागत कम करने के अवसर बढ़ते हैं।

भारत का विश्व स्तर पर पहचान बना चुका दवा उद्योग, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, तेजी से फैलता डिजिटल ढांचा, तेजी से बढ़ता नए उद्यमों का क्षेत्र और कुशल मानव संसाधन अगली पीढ़ी की चिकित्सा तकनीक विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर (एसएमडी), इंटरनेट से जुड़े चिकित्सा उपकरण, रोबोट आधारित तकनीक और दूर से जांच जैसी नई तकनीकों में भारत के पास देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए नए समाधान विकसित करने के बड़े अवसर हैं।

जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजार में विस्तार कर रही हैं, गुणवत्ता भी भारत में बने चिकित्सा उपकरणों की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। सरकार नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, मान्यता प्राप्त जांच सुविधाओं का विस्तार करने, चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी मजबूत होगी।

दुनिया के स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा देने वालों, नए उद्यमों और निवेशकों के बीच करीबी सहयोग जरूरी है। जब प्रयोगशालाओं में तैयार विचार आसानी से कारखानों तक और वहां से मरीजों तक पहुंचते हैं, तभी नए आविष्कारों को वास्तविक लाभ में बदला जा सकता है। सरकार ऐसी स्थिर और पारदर्शी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनसे शोध, निवेश, तकनीकी साझेदारी और कारोबार करना आसान हो।

भारत जैसे-जैसे विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास एक-दूसरे को और मजबूत करेंगे। एक मजबूत चिकित्सा उपकरण उद्योग उच्च मूल्य वाले उत्पादन, कुशल रोजगार, निर्यात और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय अधिक मजबूत बनेंगी।

भारत का चिकित्सा तकनीक क्षेत्र एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है। फिलहाल इसका आकार 15 से 16 अरब डॉलर है और यह करीब 12 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस वजह से यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्रों में से एक बन गया है।

विकसित भारत का लक्ष्य गुणवत्ता, नए आविष्कार और सभी को साथ लेकर चलने के आधार पर दुनिया में नेतृत्व करने पर जोर देता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नई चिकित्सा तकनीकें भारत की प्रमुख स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करें। इनमें माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, आपातकालीन चिकित्सा, कैंसर, हृदय रोग और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत लगातार एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक व्यवस्था तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल भारत में चिकित्सा उपकरण बनाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को समय पर अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत को दुनिया के एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना है।

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं।)

राजनीति में बढ़ता सोशल मीडिया और जेन जी का प्रभाव

डॉ. विश्वास तिवारी

नीट परीक्षा में कथित अनियमितता, पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर युवाओं ने जो आंदोलन किया उसने सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी को गर्व था कि उनके दल में कोई इस्तीफा नहीं लिया जाता है, उसे भी छात्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। अगर नैतिक आधार पर अपनी गलती पर धर्मेन्द्र प्रधान स्वयं इस्तीफा दे देते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। 18 से 29 साल के युवा जिन्हें जेन जी कहते है, उन्होंने बता दिया कि अगर शांति प्रिय आंदोलन किया जाए तो सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। हमारे 75 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे पहले समझ आ गया कि अगर जेन-जी युवाओं से जुड़ना है या संवाद करना है तो उन्हें इंस्टाग्राम पर आना होगा। उन्होंने लगातार तीन दिनों तक इंस्टाग्राम पर संवाद किए और अपने सभी मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम पर जाने की सलाह दी। इस उम्र में भी उनकी सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर इतनी पैनी नजर है, यही उनको सबसे अलग और बेहतर बनाता है। उन्हें यह भी मालूम है कि 2029 के आम चुनावों में जेन जी की भागीदारी 25 प्रतिशत होगी, यानि हर चौथा मतदाता जेन-जी का होगा। इसी को देखते हुए हर विपक्षी दल भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे है। अब पुराने समय में होने वाली पारंपरिक रैलियों और भाषणों के साथ-साथ सोशल मीडिया, छोटी छोटी रील्स, मीम्स पॉडकॉस्ट और इन्फलुएंसर की मदद लेना बहुत जरूरी हो गया है। इस पीढ़ी को जातीय राजनीतिक, पारंपरिक वोट, संवाद, चुनाव जीतने के लिए किए वादे पर भरोसा नहीं रहा है। उन्हें तो रोजगार, परीक्षाओं में पारदर्शिता, डिजिटल अवसर, स्टार्टअप में आर्थिक मदद, जैसे मुद्दों पर ही प्रभावित किया जा सकता है। इसी को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपनी अलग डिजिटल टीम और सोशल मीडिया कटेंट तैयार करवा रहा है। जंतर मंतर पर जो सरकार विरोधी आंदोलन हुआ उसमें अनुशासित युवाओं को देखना बहुत ही सुखद था। वह आंदोलन वाली जगह जगह पर झाड़ू लगा रहे थे, कचरा एकत्रित कर रहे थे, अपने खर्चे पर खाना लाकर बांट रहे थे। इस आंदोलन को न केवल युवाओं का समर्थन मिला, बल्कि उनके माता-पिता की सहानभूति मिली। जो दिहाड़ी मजदूर, खोमचे वाले, किसान जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी संवेदना भी इन युवाओं के साथ थी। इतने शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद उन्हें कई लोगों को जेन-जी की भाषा पर एतराज हुआ जो सही भी है। ऐसा नहीं है इन युवाओं में संस्कार नहीं है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्हें त्वरित परिणाम चाहिए।

इस आंदोलन की आड़ में कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हो गए जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की जिससे माहौल गर्मा गया और पुलिस को भी लाठी चार्ज और पेलेटगन का उपयोग करना पड़ा। जेन जी यह पीढ़ी इंटरनेट के युग में पैदा हुई है। यह फेसबुक, इंस्टाग्राम, एम्स, यू-ट्यूब और व्हाट्सएप का इस्तेमाल केवल सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं करते, बल्कि जनमत निर्माण और राजनीतिक संवाद के लिए भी कर रहे है। आजकल किसी भी संदेश या संवाद की सफलता उसकी सच्चाई पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि उसे कितनी तेजी से और कितनी क्रिएटिवीटी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल कोई भी आंदोलन, रैली या भाषण होता है तो कुछ ही समय में वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। उस पर रील्स, मीम्स और उसके ग्राफिक्स वायरल होने लगते है, चाहे वो कोई राजनेता हो, फिल्म स्टार हो या कोई खिलाड़ी। हर राजनीतिक दल के समर्थक इसे अपने नजरिए से पेश करते है। अब कोई भी आंदोलन की लड़ाई सड़क के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर भी चलती है। यह जेन-जी जनरेशन केवल पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं रहती, वह सोशल मीडिया पर भी निगाह रखती है, जो कि कई बार एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है।

इस आंदोलन में शामिल जेन जी कितने क्रिएटिव थे ये जंतर मंतर पर लगा पोस्टर बताता है। उस पर लिखा था 'हमारी शिक्षा व्यवस्था में दो ही चीजों की कमी है-पहली शिक्षा और दूसरी व्यवस्था।' यह नारा भी बहुत वायरल हुआ। जेन-जी ने सोनम वांगचुक को आंदोलन में शामिल किया जो एक परिपक्व चेहरा थे और उन्हें झुकना भी मुश्किल था। उनके शामिल होने से इस आंदोलन की गंभीरता लोगों के समझ आई। इस आंदोलन के सफल होने के कई कारण है। आंदोलन करने वाले कोई किसान नहीं थे कि अगर वो दिल्ली आ गए जो उनकी फसलें खराब हो जाएगी और ना ही इनके पास नौकरी थी कि इनके बैंक खातों की जांच होती और ना ही यह उद्योगपति थे कि इनके पीछे इनकम टैक्स या ईडी को लगाकर दबाव में डाला जाता। यह लोग तो पढ़ने वाले युवा थे जो ईमानदारी से परीक्षा देकर अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे। इन्हें न कोई पद का लालच था और ना ही पुलिस का डर था। इन्हें चाहिए तो अपनी मेहनत का परिणाम। सरकार को यह समझना होगा की इन युवाओं का गुस्सा केवल नीट पेपर लीक के कारण नहीं था, बल्कि यह उस तनाव के कारण था जो उन्हें यहां तक ले आया। रोजगार कम होने के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती महंगाई, नेताओं के झूठे वादे जो केवल चुनाव के समय ही सुनने को मिलते है, पूरे कभी नहीं होते।

सोशल मीडिया अपनी ताकत के साथ कई चुनौतियां भी लेकर आता है क्योंकि सही जानकारी के साथ यह भ्रामक और गलत सूचनाएं भी लेकर आता है। पुराने बयान, पुराने वीडियों को एडिट करके तैयार किए वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल करा दिए जाते है। अब ए.आई. के दौर में सूचना की सत्यता को पहचानना बहुत जरूरी हो गया है। गलत सूचनाएं लोकतंत्र और समाज के लिए बड़ी हानिकारक साबित हो सकती है। 2029 के आम चुनावों में सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग होगा और राजनीतिक दल को इसके अनुसार तैयारी करनी होगी।

ब्रिक्स 2026 से मध्य प्रदेश को वैश्विक सांस्कृतिक पहचान का मिला नया मंच

ब्रिक्स समूह का विस्तार अब केवल आर्थिक और राजनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संस्कृति और पर्यटन को भी वैश्विक मंच देने की दिशा में बढ़ रहा है। 2026 में मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित होने वाला ब्रिक्स पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग सम्मेलन इसी सोच का प्रमाण है, जहां करीब 100 विदेशी प्रतिनिधि 8 और 9 अगस्त को जुटेंगे और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रखेंगे। सांची के विश्व धरोहर स्तूप और भोपाल के पास स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय इस आयोजन के केंद्र में हैं और यह चयन केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की उस समृद्ध विरासत को उजागर करने की रणनीति है, जो इतिहास, कला और अध्यात्म तीनों को एक साथ जोड़ती है।

तार्किक रूप से देखें तो ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया और यूएई जैसे नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। इन देशों की कुल आबादी और आर्थिक ताकत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अगर पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से इन देशों के नागरिकों को भारत से जोड़ा जाए तो यह केवल लोगों का आवागमन नहीं होगा, बल्कि व्यापार, निवेश और आपसी समझ भी बढ़ेगी। सांची स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जो चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गहरी आस्था रखता है। वहीं भीमबेटका के 10,000 साल पुराने शैलचित्र मानव सभ्यता की शुरुआती कहानी कहते हैं। यह दोनों स्थल ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के लिए भारत की निरंतरता और विविधता को समझने का सबसे सशक्त माध्यम बनेंगे।

मध्य प्रदेश को पर्यटन के मानचित्र पर पहले से ही एक अलग पहचान मिली है। खजुराहो, बांधवगढ़, कान्हा, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे स्थल पहले से

संस्कृति अब केवल प्रदर्शन का विषय नहीं रही, बल्कि वह कूटनीति का औजार बन गई है। ब्रिक्स के मंच पर भारत अपनी सॉफ्ट पावर को आगे रखकर यह संदेश दे सकता है कि भारत विकास के साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ा है।

पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच पर सांची और भीमबेटका को रखना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अब हेरिटेज टूरिज्म को नई ऊंचाई देना चाहती है। जब विदेशी प्रतिनिधि यहां आएंगे तो उनके साथ मीडिया, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और ट्रैवल कंपनियां भी जुड़ेंगी। इससे स्थानीय होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और गाइड जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा।

सारगर्भित बात यह है कि संस्कृति अब केवल प्रदर्शन का विषय नहीं रही, बल्कि वह कूटनीति का औजार बन गई है। ब्रिक्स के मंच पर भारत अपनी सॉफ्ट पावर को आगे रखकर यह संदेश दे सकता है कि भारत विकास के साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ा है। सांची में बौद्ध शांति का संदेश है और भीमबेटका में मानवता की साझा विरासत है। जब ब्रिक्स के सदस्य देश इन दोनों को देखेंगे तो उन्हें भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक सभ्यता के रूप में दिखाई देगा और यही संबंध आगे जाकर शिक्षा, छात्र विनिमय और संयुक्त अनुसंधान में बदल सकते हैं।

चुनौती भी स्पष्ट है। आयोजन सफल हो, इसके लिए आधारभूत ढांचा, कनेक्टिविटी और आतिथ्य की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा। सांची और भोपाल के बीच परिवहन, भाषा सुविधा और सुरक्षा के मानक ऊंचे रखने होंगे। साथ ही स्थानीय कलाकारों, जनजातीय संस्कृति और बुंदेलखंडी-मालवी लोक कला को भी इस मंच पर स्थान मिलना चाहिए, ताकि प्रतिनिधि मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर लेकर जाएं।

ब्रिक्स 2026 का यह आयोजन मध्य प्रदेश के लिए केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह राज्य की संस्कृति को वैश्विक ब्रांड बनाने का अवसर है। अगर इसे सही योजना और दीर्घकालिक दृष्टि से चलाया गया तो सांची और भीमबेटका आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों के नागरिकों के लिए भारत आने का पहला कारण बन सकते हैं और मध्य प्रदेश इस सांस्कृतिक सेतु का सबसे मजबूत स्तंभ साबित हो सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

बेटियों ने रचा इतिहास, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हर स्ट्रीम में आगे

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का नक्शा इस बार पूरी तरह बदल गया है। सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और निजी कॉलेजों में हुई ऑनलाइन काउंसलिंग के आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि राज्य की बेटियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 9 लाख 95 हजार छात्रों ने विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। इनमें 4 लाख 54 हजार छात्राएं और 1 लाख 34 हजार छात्र शामिल हैं। यानी कुल प्रवेश का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा केवल छात्राओं का है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा को लेकर समाज की सोच कितनी तेजी से बदली है और बेटियां अब केवल सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि मुख्यधारा में आकर अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा साइंस स्ट्रीम की है, जो हमेशा से लड़कों का गढ़ मानी जाती थी। इस बार साइंस में 5 लाख 29 हजार छात्रों ने प्रवेश लिया। इनमें 2 लाख 81 हजार छात्राएं हैं, जबकि 2 लाख 40 हजार छात्र हैं। यानी साइंस में भी छात्राओं ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। आर्ट्स में भी यही रुझान है। कुल 2 लाख 40 हजार प्रवेश में से 1 लाख 29 हजार छात्राएं हैं और 1 लाख 11 हजार छात्र हैं। कॉमर्स की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां 3 लाख 34 हजार छात्रों ने प्रवेश लिया, जिसमें 1 लाख 83 हजार छात्राएं और 1 लाख 51 हजार छात्र हैं। यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब हर स्ट्रीम में छात्राओं की संख्या बढ़ी है और यह बढ़ोतरी केवल भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि धार, बड़वानी, सिवनी, मंडला, शहडोल और पांढुरना जैसे दूरस्थ जिलों से भी हजारों की संख्या में लड़कियों ने आवेदन किया है।

इस बदलाव के पीछे एक नहीं, कई कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सरकार की नीतियां हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए फीस की चिंता नहीं रही, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। दूसरा कारण बुनियादी सुविधाओं में सुधार है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश भर में नए शासकीय कॉलेज खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिग्री कॉलेज की पहुंच बढ़ी है। साथ ही कॉलेजों में छात्रावास, सुरक्षा कैमरे, महिला हेल्पडेस्क और परिवहन जैसी सुविधाएं बढ़ने से माता-पिता का भरोसा बढ़ा है।

सामाजिक सोच में भी बदलाव है। पहले जहां बेटियों की शिक्षा को खर्च माना जाता था, अब उसे निवेश माना जाने लगा है। माता-पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या प्रशासनिक अधिकारी बने। कोचिंग

संस्थानों और प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों के लगातार बेहतर परिणाम ने भी इस सोच को मजबूती दी है। नीट, जेईई और यूपीएससी में प्रदेश की बेटियों के टॉप करने की खबरें अब आम हैं और यही खबरें गांव की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। तकनीक ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण अब गांव की लड़की भी ऑनलाइन क्लास और करियर गाइडेंस तक पहुंच बना लेती है।

लेकिन इतने सकारात्मक आंकड़ों के बीच कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल गुणवत्ता का है। जब एक साथ लाखों छात्राएं प्रवेश ले रही हैं तो क्या हमारे कॉलेजों में उतने शिक्षक हैं? क्या प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम की सुविधा पर्याप्त है? कई जिलों से यह शिकायत आ रही है कि एक प्रोफेसर पर 80 से 100 छात्रों का बोझ है और विज्ञान विषयों में प्रैक्टिकल के लिए उपकरण नहीं हैं। अगर प्रवेश के साथ गुणवत्ता नहीं बढ़ी तो डिग्री केवल कागज बनकर रह जाएगी।

दूसरा सवाल रोजगार का है। साइंस और कॉमर्स में प्रवेश तो बढ़ गया, लेकिन इन पाठ्यक्रमों से निकलने के बाद छात्रों के लिए कितने अवसर हैं? आर्ट्स में तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां डिग्री के बाद सीधे रोजगार के विकल्प कम हैं। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास विभाग को मिलकर स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे। हर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल बनानी होगी और उद्योगों के साथ जुड़कर इंटर्नशिप के अवसर देने होंगे। तभी प्रवेश का यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था में तब्दील हो पाएगा।

तीसरा सवाल ड्रॉपआउट का है। आंकड़े बताते हैं कि प्रवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले सेमेस्टर के बाद कई छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं। कारण पारिवारिक दबाव, आर्थिक तंगी या कॉलेज तक आने-जाने की समस्या होती है। इसके लिए छात्रावास की संख्या बढ़ानी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था देनी होगी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग की सुविधा भी जरूरी है, ताकि लड़कियां पढ़ाई के दबाव को संभाल सकें।

अब समय आ गया है कि हम केवल प्रवेश के आंकड़े न देखें, बल्कि आउटकम पर फोकस करें। यानी कितनी छात्राओं ने डिग्री पूरी की, कितनों को रोजगार मिला और कितनों ने उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाया। इसके लिए हर जिले में डेटा सेंटर बनाना होगा, जहां हर छात्रा की प्रगति को ट्रैक किया जा सके। साथ ही निजी क्षेत्र को भी आगे आना होगा और छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप, मेंटरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे।

इस पूरे परिदृश्य में मध्य प्रदेश के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर राज्य ने इस महिला शक्ति को सही दिशा दी तो आने वाले दस वर्षों में मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां महिला साक्षरता, रोजगार और नेतृत्व तीनों में सबसे आगे होगा। बेटियां जब शिक्षित होंगी तो न सिर्फ अपना परिवार आगे बढ़ाएंगी, बल्कि समाज की कुरीतियों को भी तोड़ेंगी और अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान देंगी।

साइंस में 5 लाख और कॉमर्स में 3 लाख से ज्यादा छात्राओं का प्रवेश लेना केवल एक शैक्षणिक घटना नहीं है। यह एक सामाजिक क्रांति है। यह उस नए मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां बेटी बोझ नहीं, बल्कि गर्व है। सरकार को अब इस गति को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता, रोजगार और सुरक्षा के तीन स्तंभों पर काम करना होगा। कॉलेजों को उद्योगों से जोड़ना होगा, पाठ्यक्रमों को बाजार की जरूरत के अनुसार बदलना होगा और सबसे जरूरी, समाज को यह भरोसा दिलाना होगा कि पढ़ी-लिखी बेटी ही सशक्त परिवार और सशक्त राष्ट्र की नींव है। अगर हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देते तो आने वाला दशक मध्य प्रदेश की बेटियों का दशक होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)